

Q (1.) भारतीय संविधान में शिक्षा के समवर्ती स्तर को बताइये।

Ans: - भारत के संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा से संबंधित कर्तव्यों और दायित्वों का वर्णन किया गया है। इसलिये सरकार केन्द्रीय, राज्य एवं स्थानीय तहसील स्तर पर शिक्षा से संबंधित सभी कार्यों को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगी। भारत का संविधान एक संघीय संविधान है जिसमें केन्द्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों को बाँटा गया है। इस वंश के कारण भारतीय संविधान में तीन शक्तियाँ तैयार की गई हैं। इनके अनुसार संघ एवं उनके अधीनस्थ शैक्षिक क्रियाकलापों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह की योजना प्रस्तुत की गई है। यद्यपि हमारे संविधान में 1935 के भारत सरकार अधिनियम को शब्दशः स्वीकार किया है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक राज्य सरकार को शिक्षा के प्रति जवाबदेह ठहराया गया है, किन्तु कुछ कार्य एवं उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार के प्रति भी सुनिश्चित किये गये हैं। इससे संबंधी तीन शक्तियाँ निम्नलिखित हैं: -

① केन्द्रीय शक्ति: - इस शक्ति के अन्तर्गत जो विषय शामिल हैं, अर्थात् केन्द्र के संदर्भ में केन्द्र सरकार कानून निर्माण कर सकती है। इनमें से प्रविष्टि 62, 63, 64, 65 एवं 66 शिक्षा से संबंधित हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार स्वतंत्र रूप से अपने अधीन रख सकती है। प्रमुख प्रविष्टियाँ निम्न हैं।

(a) प्रविष्टि 63 - इस प्रविष्टि का राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा संस्थाओं एवं अन्य विधि-सम्मत तरीके से संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय संस्थाओं के वर्चस्व की देख रेख एवं सुरक्षा का कार्य सुनिश्चित किया है।

(b) प्रविष्टि 64 - "भारत सरकार द्वारा पुर्णतः या आंशतः पोषित वैज्ञानिक या प्राविधिक शिक्षा की संस्थाएँ और संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएँ।"

② राज्य शक्ति: - संविधान के 43वें संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 52 द्वारा शिक्षा संबंधी प्रविष्टि 11 का लोप किया गया है और शिक्षा की समवर्ती शक्ति में शामिल किया गया है। रीति-नीति कारिणीय केन्द्र के हाथ में है और विवाद की स्थिति में केन्द्र का निर्णय कानून ही मान्य होगा परन्तु अभी भी प्रत्येक राज्य शिक्षा क्षेत्र का संचालन कर रहा है। इस राज्य शक्ति में 66 विषय उद्घृत हैं, जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाने का निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। इस संदर्भ में 19वीं प्रविष्टि में व्यक्त किया गया है कि राज्य सरकार शिक्षा के प्राथमिक-माध्यमिक-लिखित के प्रति भी उत्तरदायी हैं - राज्य निर्गमित आर्किटेक्चर, पुस्तकालय, संग्रहालय, या अन्य समतुल्य संस्थाएँ, जो संसद द्वारा विधि

सम्मत या अधीनस्थ ही तथा राष्ट्रीय महत्व की चिन्तित की गई हो, ये निम्न प्राचीन और ऐतिहासिक ज्ञान और अभिलेख ।

③ समवर्ती सूची :- समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 25 का यह उल्लेख "सूची 1 की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 के उपबंधों के अधीन रहते हुए शिक्षा जिसके अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय हैं, अभिकर्ता का व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण ।" इसका अर्थ यह हुआ जब भी शिक्षा के संबंध में कोई वाद-विवाद होगा तो केन्द्र का कानून एवं अभिमत सर्वोपरि होगा । यह स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र के वर्चस्व को पुष्ट करती है ।-

संविधान में इस सूची के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों का समावेश किया गया है :-

(a) आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन

(b) व्यावसायिक एवं प्राविधिक प्रशिक्षण ।

(c) वैज्ञानिक अनुसंधान ।

(d) प्राविधिक शिक्षा ।

(e) हिन्दी भाषा का विकास एवं समुन्नयन ।

(f) राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण ।

(g) संस्कृत साहित्य का संरक्षण ।

(h) विकलांग शिक्षा का विकास ।

(i) शैक्षिक अनुसंधानों का विकास ।

(j) अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक हितों की रक्षा ।

(k) अनुसूचित जातियों, क्षेत्रों एवं वर्गों हेतु शिक्षा का विकास ।

(l) राष्ट्रीय एवं संवैधानिक एकता ।

(m) प्रगतिशील दार्शनिक हेतु दार्शनिक व्यवस्था ।

(n) ग्राम व्यावसायिक शिक्षा ।

(o) केन्द्रीय अनुसंधान एवं अभिकर्ताओं की स्थापना ।

(p) 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ।

Q(2) राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या करें ?

Ans: - किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सर्वप्रथम ये आयरलैंड के संविधान में लागू किये गये थे। ये तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किए गये हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। निर्देशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वे तत्व हैं, जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है।

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।

जनकल्याणकारी राज्य वह है जो जनकल्याण हेतु ही अस्तित्व में आया है यह ही कार्य करता है।

① दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्य तथा कानून व्यवस्था बनाये रखना।

② जनता के आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देना।

इसका अर्थ यह है कि आर्थिक विकास व्यक्तिगत मामला नहीं रहकर राज्य की जिम्मेदारी है कि वह व्यक्तियों के आर्थिक विकास को बढ़ाने का कार्य करे। इन नीति निर्देशक के आधार पर राज्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन पर उसे चलना है। ये तत्व एक स्की-कृत सामाजिक, आर्थिक प्रशासनिक कार्यक्रम का निर्धारण भी राज्य हेतु करते हैं।

इन तत्वों की प्रकृति: -

अनुच्छेद 37 के अनुसार ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाये जा सकते यह तत्व वैधानिक न होकर राजनैतिक स्वरूप रखते हैं तथा मात्र नैतिक अधिकार रखते हैं। वे न तो कोई वैधानिक बाधता ही राज्य पर लागू करते हैं न जनता हेतु अधिकार, कर्तव्य। वे मात्र राज्य के लिए ऐसे सामान्य निर्देश हैं कि राज्य कुछ ऐसे कार्य करे जो राज्य की जनता के लिए लाभदायक हों। इन निर्देशों का

पालन कार्यपालिका की नीति तथा विधायिका की विधियों से हो सकता है।

मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में भेद : —

- ① मौलिक अधिकार राज्य की नकारात्मक शक्ति का वर्णन करते हैं तथा राज्य को कुछ विशेष कृत्य करने से रोकते हैं। वहीं ये तत्व राज्य की नकारात्मक शक्ति, दायित्व का वर्णन करते हैं तथा राज्य से अपेक्षा करते हैं कि वह जनकल्याण हेतु विभिन्न प्रयास करें।
- ② मौलिक अधिकार देश में राजनैतिक जनतंत्र स्थापित करते हैं वहीं ये तत्व देश में सामाजिक आर्थिक जनतंत्र लाते हैं।
- ③ मौलिक अधिकार जनता को दिये जा चुके हैं वहीं निर्देशक तत्व निर्देशात्मक हैं जो ~~अधिकारों~~ अधिकारों की चर्चा तो करते हैं परन्तु वास्तव में देते कुछ नहीं हैं।
- ④ मौलिक अधिकार कई वैधानिक शब्दों में वर्णित हैं जबकि तत्व मात्र सामान्य भाषा में।
- ⑤ दोनों की न्यायालय में स्थिति पूर्णतः भिन्न है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्देशक तत्व 39 ब तथा 39 हैं। अनु 39 ब के अनुसार राज्य के संसाधन इस प्रकार प्रयोग ही कि उनका लाभ जनसंख्या के सभी भागों को प्राप्त हो। अनु 39 ब कुछ व्यक्तियों के घबों में धन के केन्द्रीकरण को रोकता है। अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्राप्त करने लायक तो नहीं बताते हैं परन्तु देश के शासन में इन्हें मौलिक रूप में निहित मानते हैं। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह इन तत्वों को अपनी नीतियों तथा संवद द्वारा बनाये कानून में स्थापित करे।

अनुच्छेद 31 ब के अनुसार कोई विधि-लोकसु-
च्छेद 'ब' 'घ' को प्रभावित करती है किसी भी न्यायालय में परीक्षित नहीं की जा सकेगी। केशवानंद भारती वाद में इस संशोधन को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अनु 31 ब के प्रथम भाग को वैध मान लिया किन्तु दूसरे भाग को इस आधार पर खारिज कर दिया क्योंकि वह न्यायपालिका की पुनरीक्षण शक्ति दीन लेती है जो कि संविधान के मूल ढाँचे का भाग है।

Q(3) शिक्षा के अधिकार नियम 2009 पर रिपनी लिखें :-

Ans:- वास्तव में शिक्षा जो एक संवैधानिक अधिकार था उसे अब एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत मान्यता दी गई थी जिसके अनुसार "राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, शिक्षा और बेरोजगारी, स्वास्थ्य, बीमारी और विकलांगता के मामले में सर्व-जनिक सहायता करने के लिए काम करते हैं।"

शिक्षा का अधिकार से तात्पर्य शिक्षा को एक अधिकार के रूप में प्रदान करना है। सरकार ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए अलग-अलग कदम उठाए और इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए तथा शिक्षा को सर्वपुलभ बनाने के लिए 2002 में संविधान के (86वें संशोधन) अधिनियम भाग III में एक नया धारा 21 A जोड़ी गई। इस धारा के अधीन निम्न प्रावधान बनाए गए -

- ① प्राथमिक शिक्षा अब सभी का मूलभूत अधिकार है।
- ② 6-14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी।
- ③ यह एक कानून है। इसे एक संकल्प के रूप में आवश्यक ही लागू करना होगा।
- ④ भारत में प्रत्येक राज्य की अलग संरचना व वातावरण होने के कारण राज्य अपने अनुसार इसे लागू कर सकते हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम :-

शिक्षा किसी भी व्यक्ति एवं समाज के समग्र विकास तथा सशक्तिकरण के लिए आधारभूत मानव मौलिक अधिकार है। यूनेस्को की शिक्षा के लिए वैश्विक मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2000 के मुताबिक, लगभग 135 देशों ने अपने संविधान में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है तथा मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा सबको देने का प्रावधान किया है। भारत ने 1950 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा देने के लिए संविधान में प्रतिबद्धता का प्रावधान किया था। इसे अनुच्छेद 45 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है।

12 दिसम्बर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया।
और इसके अनुच्छेद 51A को संशोधित करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है।

बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 1 अप्रैल 2006 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को पूर्णतः मुफ्त एवं अनिवार्य कर दिया गया है। अब यह केन्द्र तथा राज्यों के लिए बाध्यता है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा सभी को सुलभ ही रहे।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं :-

- ① 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे के लिए नजदीकी विद्यालय में मुफ्त आधारभूत शिक्षा अनिवार्य है।
- ② इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें शुल्क भुगतान करने की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से रोका जा सकेगा।
- ③ यदि 6 से अधिक उम्र का ^{बच्चा} किसी कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा।
- ④ इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए संवैधानिक सरकार तथा स्थानीय प्रशासन को यदि आवश्यक हुआ तो विद्यालय भी खोलना होगा। अधिनियम के तहत यदि किसी क्षेत्र में विद्यालय नहीं हैं तो वहाँ पर तीन वर्षों के तय अवधि में विद्यालय का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
- ⑤ इस अधिनियम के प्रावधानों को अमल में लाने की जिम्मेदारी केन्द्र एवं राज्य सरकार, दोनों की है, तथा इसके लिए होने वाला खर्च भी इसकी समवर्ती जिम्मेदारी रहेगी।

यह अधिनियम प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक शिक्षा तथा बच्चों तक शिक्षा पहुँचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम का सर्वाधिक लाभ शहरी के बच्चे, बाल मजदूर, प्रवासी बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जो सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, भाषाई अथवा लिंग कारणों की वजह से शिक्षा से वंचित बच्चों को मिलेगा। भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाने का कदम ऐतिहासिक कहा जा सकता है तथा यह तब ही होगा कि देश वैश्व स्तर पर लक्ष्य तथा सभी के लिए शिक्षा के नजदीक पहुँच रहा है।

Q(4.) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं?

Ans:- सन् 1985 ई० में तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री ~~राजीव~~ राजीव गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने की घोषणा की थी। मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज प्रकाशित किया गया और नवंबर 1986 में इसकी कार्य योजना प्रकाशित की गई।

"नई शिक्षा नीति (1986) हमारे देश के लिए एक पर्याप्त चरित्र है।" इस कथन को शिक्षा नीति के विवेचन के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है।
(1) राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा को विशेष महत्व :- किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। इस शिक्षा नीति में शिक्षा को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर इतना महत्व दिया गया और शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। शिक्षा के विभिन्न चरणों के सुदृढीकरण और उन्हें देशकाल की परिस्थिति के अनुकूल बनाने का निश्चय किया गया।

(2) शिक्षा की व्यवस्था के लिए पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था - इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रमुख के शैक्षिक, आध्यात्मिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अतः राष्ट्रीय में शिक्षा की व्यवस्था के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना स्वीकार किया गया।

(3) समपूर्ण राष्ट्र में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू :- इस शिक्षा नीति के अंतर्गत विभिन्न-विभिन्न प्रांतों में अलग-अलग प्रकार की शैक्षिक संरचना थी। इस शिक्षा नीति में 10+2+3 शिक्षा संरचना समूचे देश के लिए स्वीकार की गई।

(4) व्यवसायिक शिक्षा की प्रचुरता - शिक्षा प्रणाली ने व्यवसायिक शिक्षा को अधिक प्रचुरता दी है। इस प्रणाली के द्वारा दात्र स्वयं के प्रति जागरूक होना। कार्यकुशल के अंतर्गत देशों के द्वारा अपनी रूचि के अनुसार व्यवसाय प्रारंभ कर सकेंगे। इस व्यवसायिक कुशलता के द्वारा देश में व्याप्त बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है।

(5) शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल - नई शिक्षा नीति में अमान्यता को दूर करने तथा उन लोगों को शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने पर बल देते, जिन्हें समानता से दूर रखा गया है। नाशियों, अनुपुत्रित जाति और विकलांगों की शिक्षा की विविध व्यवस्था की जायेगी व सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान किया जायेगा।

(6) शिक्षकों के स्तर व शिक्षक-प्रशिक्षण में सुधार पर बल - इस शिक्षा नीति में, शिक्षकों के स्तर को उंचा उठाने के लिए उनके वेतनमान वृद्धि जायेगी और सेवा शर्तों को आकर्षक बनाया जायेगा, की घोषणा की गयी।

प्रत्येक जिला में ॥ जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIE) की स्थापना की जायेगी जिसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी।

⑦ परीक्षा प्रणाली एवं प्रत्यांकन प्रक्रिया में सुधार :- इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है कि प्रत्यांकन को एक सतत प्रक्रिया बनाया जायेगा और बाह्य प्रत्यांकन के स्थान पर आंतरिक प्रत्यांकन को अधिक प्रश्वर दिया जायेगा।

⑧ उच्च शिक्षा का प्रचार व जनयन :- वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के प्रचार व जनयन पर जोर दिया जायेगा। उच्च शिक्षा संस्थाओं की सुविधाओं के विस्तार व कृत्रीकरण पर बल दिया जायेगा।

⑨ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था - इस स्तर की शिक्षा में शिक्षकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास, भोजन, वस्त्र, सफाई और पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा इनके लिए खेलकूद व व्यायाम की उचित व्यवस्था की जायेगी। इस स्तर की शिक्षा के बुनियाद को प्रजबूत किया जायेगा। जिससे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सके।

⑩ नवोदय विद्यालय की स्थापना :- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किए गए संकल्प (ज्ञानि - निर्धारक) विद्यालय की स्थापना को पूरा करने के लिए नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक प्रि:शुल्क व आवासीय पदाई की व्यवस्था होगी। ये विद्यालय केन्द्रीय प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबन्धित होंगे। इस विद्यालय में दान - दानाओं की अद्याय, भोजन, पुस्तकें, पाठ्य सामग्री तथा गणवेश भी प्रि:शुल्क प्रदान किया जायेगा।

अतः हम कह सकते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र में जोड़े हुए प्रत्येक पहलुओं पर विचार-विमर्श का उनकी समस्याओं हेतु समाधान देने का प्रयास किया गया है। वह चाहे पाठ्यक्रम ही या पाठ्य-पुस्तक या फिर शिक्षक व शिक्षण संबंधी हो। इस नीति में यह (होना चाहिए) के स्थान पर (किया जायेगा) पर बल दिया गया है।

Q. (5) माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुद्रालियर कमीशन) की व्याख्या करें ?

Ans: - स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप में नवीन विचारों, मूल्यों एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। जिससे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष डॉ० ए० एल० मुद्रालियर की अध्यक्षता में वर्ष 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। यह आयोग मुद्रालियर आयोग के भी नाम से जाना जाता है। तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप, उनकी विशेषताओं, कमियों एवं आवश्यक परिवर्तन को जानने की शक्ति से मुद्रालियर आयोग का गठन किया गया था। चूंकि माध्यमिक शिक्षा निचले स्तर पर प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च स्तर पर विश्वविद्यालय से जुड़ी होती है। इस कारण केवल माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप संशोधन को ध्यान देना पर्याप्त नहीं था। इसी कारणवश मुद्रालियर आयोग ने प्राथमिक एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा का एक नवीन स्वरूप प्रस्तुत किया जो निम्नलिखित है :-

(1) माध्यमिक शिक्षा की अवधि नव वर्ष की होनी चाहिए।

(2.) माध्यमिक शिक्षा की अवधि निम्न दो स्तरों में विभक्त की जानी चाहिए :-

(a) 3 वर्ष का मिडिल या बुनियादी माध्यमिक या सीनियर बैसिक स्तर।

(b) 4 वर्ष का उच्चतर माध्यमिक स्तर

(3.) डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष की कर दी जानी चाहिए।

(4.) माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 वर्ष तक की अवस्था के बालक - बालिकाओं के लिए होनी चाहिए।

(5.) वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षाओं को अंग का दिया जाना चाहिए।

उनकी 11 वीं कक्षा को हाई स्कूल से तथा 12 वीं कक्षा को कॉलेज से संबद्ध कर दिया जाना चाहिए।

(6.) ग्रामीण स्कूलों में कृषि शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार करना चाहिए। अतः इन स्कूलों में उद्यान-विज्ञान, पशुपालन एवं कृषि उद्योग-चाँचों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(7.) बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। इन स्कूलों में पाठ्यक्रम का विभिन्निकरण किया जाना चाहिए ताकि छात्र अपनी विभिन्न उद्देश्यों, रुचियों और योग्यता के अनुसार

पाठ्यक्रम का चयन कर सके ।

⑧ औद्योगिक क्षेत्रों में टेक्निकल स्कूलों की स्थापना प्थात संख्या में की जानी चाहिए ।

⑨ सब बालिका विद्यालयों में बालिकाओं की ग्रह-विज्ञान के अध्ययनों की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ।

⑩ बड़े नगरों में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाना चाहिए ।

माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य :-

① व्यावसायिक कुशलता में उन्नति :- माध्यमिक शिक्षा का पहला उद्देश्य छात्रों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना होना चाहिए अतः माध्यमिक शिक्षा में औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए । इन विषयों की शिक्षा से छात्र और देश दोनों का हित होगा ।

② नेतृत्व का विकास :- माध्यमिक शिक्षा का दूसरा उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना चाहिए । अतः माध्यमिक शिक्षा का आयोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे छात्र सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक व्यावसायिक और राजनीतिक क्षेत्रों में नेतृत्व का योग्यता ग्रहण कर सके ।

③ जनसंघीय जागरूकता का विकास :- माध्यमिक शिक्षा का तीसरा उद्देश्य छात्रों में जनसंघीय जागरूकता का विकास करना होना चाहिए । अतः माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे छात्रों में अनुशासन, देश-प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता आदि गुणों का विकास हो

④ व्यक्तित्व का विकास :- माध्यमिक शिक्षा का चौथा और अंतिम उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होना चाहिए । अतः माध्यमिक शिक्षा का संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे छात्रों का साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक विकास हो सके ।

Q(6) रामशर्मा निरीक्षण कमेटी 1990 पर नोट लिखिए ।

Ans:- मई 1986 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई और उसी वर्ष अक्टूबर माह में इसकी कार्ययोजना प्रकाशित की गई, और 1987 में इसे क्रियान्वित करना शुरू कर दिया गया। इसी बीच 1989 में केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा कता में आ गया। सरकार के बदलते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन की वाकफ उठी। और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मई 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए आचार्य रामशर्मा की अध्यक्षता में एक 17 सदस्यीय समिति का गठन किया। इसे रामशर्मा समिति 19-90 कहा जाता है। सरकार ने इस समिति को तीन कार्य सौंपे :-

- ① राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करना।
- ② 1986 की नीति में संशोधन के लिए सुझाव देना।
- ③ संशोधित नीति के क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना।

समिति ने अपनी रिपोर्ट :- "प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर" शीर्षक से 26 दिसम्बर, 1990 में प्रस्तुत की। इस समिति की रिपोर्ट के प्रारंभ में यह स्वीकार किया गया है कि 1986 के बाद देश की स्थिति और अधिक खराब हुई है, सांस्कृतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। समता के स्वान पर वर्ग-भेद बढ़ रहा है। इस समिति ने सम्पूर्ण अध्ययन करने के उपरान्त यह पाया कि 5 मुद्दे ऐसे हैं जिनका हल नहीं निकल पाया जो कि निम्न हैं :-

- ① निरक्षरता को दूर करना।
- ② शिक्षा को रोजगार-सुरवी बनाना।
- ③ सामाजिक समानता लाना।
- ④ देश के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना।
- ⑤ प्रकृतिक विचारधारा, शोषण, ईश्या भेष की भावना का सँघर्ष।

इन समस्याओं का हल निकालने के लिए आयोग ने निम्न सुझाव दिये।

① वित्त सँलक्षी सुझाव :- आयोग ने देखा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए 7.8 प्रतिशत की व्यवस्था की गई थी। जो कि 1985-90 में 3.55 प्रतिशत रह गई। धन की कमी के कारण शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं हो पा रहा है। इसलिए शिक्षा के लिए कम से कम 6 प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिए।

② पूर्व प्राथमिक शिक्षा सँलक्षी सुझाव व समीक्षा - शिशु देखभाल व शिक्षा (Early Childhood Care and Education) - ECEE को बढ़ावा

दिया जाये तथा अंग्रेजवादी को प्रोत्साहित किया जाये। ECE
को न्युनतम आवश्यक कार्यक्रम में जोड़ा जाये। प्रत्येक प्राथ-
मिक विद्यालय के पास शिक्षु देखभाल व शिक्षा केन्द्र खोले जायें।

③ प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव :- प्राथमिक शिक्षा का
सार्वभौमिकरण किया जाये। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की गति
प्रदान की जाए। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन
की समस्या का समाधान किया जाये।

④ माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव :- 1986 के नीतिकी
समीक्षा के उपरान्त पाया कि 1990 तक 10+2+3 योजना
ठीक से लागू नहीं हो पायी है। 26 प्रतिशत नवोदय विद्यालय
खोले गये थे जहाँ पर 25 प्रतिशत छात्रों को व्यवस्थित शिक्षा
देने का लक्ष्य था वहीं पर केवल 2.5 प्रतिशत छात्र ही उसका
लाभ उठा पा रहे हैं। इसके लिए नवोदय विद्यालय का पुनर्गठन
किया जाये। नवोदय विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार किए
जाये, आगे नवोदय विद्यालय न खोले जायें।

⑤ उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव :- 1986 की नीति के अन्वय
में पाया कि उच्च शिक्षा का स्तर तेजी से गिर रहा है। उच्च
शिक्षा में प्रवेश के नियम ठीक नहीं हैं व विश्वविद्यालय नि-
श्चयों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए समिति
ने सुझाव दिया कि प्रवेश प्रक्रिया चयन प्रक्रिया के अनुसार
ही। मान्यता देने के लिए कठोर नियम बनाये जायें व जो
मानक पूरे न कर रहे हों, उनकी मान्यता निलम्ब कर दी जाये।
शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नियुक्ति के बाद प्रशिक्ष-
ण की व्यवस्था की जाये।

⑥ प्रौढ़ शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा संबंधी सुझाव :-
बालिका शिक्षा का प्रवर्धन किया जाये। प्रौढ़ शिक्षा का उन्न-
तयित्व मात्रक संसाधन मंत्रालय के शिक्षा विभाग, ग्रामीण
विकास मंत्रालय व अन्न मंत्रालय, इन तीनों के ऊपर होता चक्री
प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार प्रौढ़ों के विकास संबंधी आव-
श्यकतायें होती चाहिए।

अन्य बात यह सच है कि राष्ट्रपति कांग्रेस ने 1986
की नीति बिन्दुओं पर ही विचार किया। उन्होंने कहा कि ये नीति
पर अमल नहीं हुआ है अतः होता चाहिए।

Q (7) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) पर लिखनी करें।

Ans: - RMSA 15-16 वर्ष की आयु के सभी युवाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता-युक्त माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने, इसमें पहुँच बनाने और उसे वहन करने योग्य बनाने के उद्देश्य से मार्च 2009 में भारत की गई मुख्य योजना है। वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् स्कूलों में आर्ट्स-सीरी, लालिका इत्यादि, माध्यमिक स्तर पर शिक्षाकर्मियों के लिए लगावेली शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा का RMSA के तहत समावेशन कर दिया गया था।

RMSA के तहत इन योजनाओं के समावेशन से योजनाओं के तहत प्रावधानों का प्रशासनिक सुव्यवस्थिकरण और महत्वपूर्ण विनियम लक्ष्य हुई। एक तरफ RMSA के तहत निधि की उपलब्धी भी बढ़ी और दूसरी तरफ इन योजनाओं के तहत किए गए इतिहास, लक्ष्यता प्राप्त स्कूलों तक पहुँचे जिनसे उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र को भी सम्मिलित किया, RMSA के तहत समावेशन से लक्ष्यता प्राप्त स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक क्षेत्र के समावेशन से RMSA का अधिकतर आधारित कार्यान्वयन भी हुआ।

माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिक रूप उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने मार्च 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसे सर्व शिक्षा अभियान-2 भी कहते हैं की शुरुआत की। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य माध्यमिक कक्षाओं (कक्षा 8-10) के स्तर को केंद्र बनाया है। माध्यमिक शिक्षा का इतिहास अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा 14-18 आयु वर्ग के युवाओं को प्रदान करने से है। इसी इतिहास को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किये जाते हैं: -

(1) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अनुसार प्रत्येक 5 किलोमीटर पर माध्यमिक विद्यालय तथा 7-10 किलोमीटर पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।

(2) माध्यमिक शिक्षा वर्ष 2017 तक सार्वभौमिक रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।

(3) समाज में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, लालिकारं तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले असह्यम लालकों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सभी को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

* राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य :-

(1) सरकारी, अर्ध-सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विनीय सहायता प्रदान की जाये ताकि माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएँ तथा अन्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

(2) प्रत्येक 5 किलोमीटर पर माध्यमिक विद्यालय तथा 7-10 किलोमीटर पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाये ताकि सभी छात्रों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध हो सके।

(3) ऐसे उपाय किये जायें ताकि लिंग, सामाजिक-आर्थिक स्तर, आसन्नता अन्य किसी भी आधार पर बालक को माध्यमिक शिक्षा से वंचित न किया जाये।

(4) लौकिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिगम के द्वारा माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके।

(5) यह निश्चित करना कि सभी छात्र जो माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वह उत्तम गुणवत्ता की हैं।

तथापि, अभी तक सहायता प्राप्त स्कूलों को दिए जाने वाले लाभ, वर्तमान R.M.D.N के प्रावधानों के मुख्य चरणों के विरोध और अन्य योजनाओं के तहत वर्तमान हस्तक्षेपों तक सीमित होंगे, राज्य स्तर पर अभि-सरण से शकीकृत और समावेशी (सहायता प्राप्त स्कूल और उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं) योजना बन पाएगी और उनका कार्यान्वयन ही पाएगा।

Q(8.) वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं ? विस्तार से व्याख्या करें :-

Ans:- वैश्वीकरण लोगों के बीच एकीकरण की एक प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में विभिन्न कंपनियों, देशों, प्रकारों, संस्कृतियों का समन्वयिकरण है, यह राजनैतिक आर्थिक शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास की प्रणाली है, आज विश्व की निवेश द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सुचना प्रौद्योगिकी तकनीकी सहायता प्राप्त करके नागरिकों को प्रेरित कर समृद्ध बनाना मानव समाज की उन्नति करना ।

वैश्वीकरण कोई नया सम्प्रत्यय नहीं है, बल्कि यह कई वर्षों से चली आ रही प्रक्रिया है। वैश्वीकरण का अर्थ हम इस प्रकार से लगा सकते हैं कि आज सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक शैक्षिक संबंध ऐसे हैं, जो राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर देशों के बीच की दूराइयों और भाषाओं को निघारित करती है, दुनिया की इस बदली आत्मनिर्भरता को ही वैश्वीकरण या अग्रपडलीकरण कहा जा सकता है। जीवन के विविध क्षेत्रों में सम्पूर्ण दुनिया के हस्तक्षेप को आज सहज ही स्वीकार कर लिया है यह वैश्वीकरण समकालीन दुनिया की सच्चाई है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी का कथन याद आता है कि "मैं नहीं चाहता कि मेरा प्रकृत चारों ओर दीवारों से घिरा हो, मेरी रिश्कियाँ बंद ही मैं तो चाहता हूँ कि सभी देशों की संस्कृतियों की हवायें मेरे घर में झिन्नी भी आजादी से बह सकें वहाँ, लेकिन यह भी नहीं चाहता कि उनमें से कोई हवा मुझे मेरी जड़ों से उखाड़ दे। वैश्वीकरण समता-याय और विश्व बन्धुत्व के आधार पर होनी चाहिए।

भारतीय प्राचीन ग्रंथों से यह स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण की परिभाषा प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध है।

आश्वर्ववेद :- सर्व भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निराशयाः ।

सर्व मद्रापी पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाय भवेत् ॥

सभी सुखी रहें, सभी निर्भय रहें सभी का कल्याण हो कोई भी दुखी हो

चैम्बर अल्ट्रकोश के अनुसार :- वैश्वीकरण अर्थात् विश्वव्यापी बना देना या सम्पूर्ण विश्व अथवा सभी लोगों को प्रभावित करना ।

वैश्वीकरण एवं शिक्षा :- जिस प्रकार नये प्रकार बनाने में जीव का मजबूत होना आवश्यक है उसी प्रकार मनुष्य के बचपन के संस्कार जितने अच्छे होंगे उतना ही उसका जीवन उत्तम रहेगा ।

शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है व्यक्ति राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक होता है। इसलिए पहले व्यक्ति को जागरूक बनाना चाहिए उसे संस्कार, मूल्य, संस्कृति सभ्यता की शिक्षा देनी चाहिए। जैसे मनुष्य का विकास होगा वैसे ही वह विश्व विकास में सहयोग देगा। आज के युग की आवश्यकता है तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा इससे मानव का विकास होता है और उसे सम्पूर्ण सृष्टि को जानने की प्रेरणा मिलती है, आज के युग में संस्कृति, सभ्यता मूल्य आधारित शिक्षा से भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य तकनीकी, विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा हो गयी है। शिक्षा की इस नयी विचारधारा के विकास के साथ ही साथ वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विकास भी हुआ है, जिससे यह एक दूसरे से प्रभावित होता है। वैश्वीकरण की सफलता का मूल आधार सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति के आचरण एवं उसके मूल्यों पर निर्भर करती है अतः मानव मूल्य एक ऐसी आचार संहिता या सद्गुण समूह है जिसे अपने संस्कारों तथा पर्यावरण के माध्यम से अपनाकर मनुष्य ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनी जीवन शैली का निर्माण किया है, वैश्वीकरण में अपना योगदान दे रहा है, शिक्षा के माध्यम से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिल रहा है।

वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव के वर्तमान समय में जितने लाभ इच्छित होते हैं वही इकती और कहीं न कहीं कुछ खतरे भी इसके प्रभाव के कारण उत्पन्न हो गये हैं। वैश्वीकरण के कारण जीवन में संतोष को सबसे कँचा स्थान देने वाली भारतीय सभ्यता एवं शैली में परिवर्तन आ गया है। आज लोग पश्चात्य जीवन शैली को श्रेष्ठ मानने लगे हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना का ह्रास होता जा रहा है। आज क्षण प्रति क्षण संपन्नरित होती जीवन चर्चा में क्या चुने क्या नहीं यह प्रश्न अत्यंत जटिल बन चुका है। न्यून कीमतों में खरीदने की इच्छा स्वदेशी एवं महंगे उत्पाद की तुलना में सस्ते एवं विदेशी उत्पाद को क़य करने (खरीदने) की इच्छा को बढ़ावा देती है। यहाँ शिक्षा को भी एक उत्पाद के रूप में मान लिया गया है। यह चिन्ता का विषय है कि इसके दुर्गामी परिणाम कितने घातक होंगे।

Q(9) दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता एवं इसकी समस्याओं को दूर करने वाली विधियों की व्याख्या करें।

Ans: - दूरस्थ शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है - दूर स्थित शिक्षा। दूर का अर्थ है जिनमें संपर्कता न हो। अर्थात् दूर से व्यवहार परिवर्तन, या परिपक्वता का अध्ययन, कुछ विद्वान इसे दूर अध्ययन व ग्रह अध्ययन भी कहते हैं।

शिक्षा की निरीपचारिक प्रणाली जिनके द्वारा उन बच्चों, युवकों, प्रौढ़ों को शिक्षा दी जाती है जो किसी कारणवश शिक्षण संस्थानों से औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं और उनमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व लगन है।

दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता के निम्न कारण हैं: -

① जनसंख्या का विस्फोट : - जनसंख्या वृद्धि के कारण विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि होना स्वभाविक है। जितनी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है उस अनुपात में शिक्षण संस्थान नहीं खोले जा सकते। अतः विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को शिक्षित करने के लिए दूरस्थ शिक्षा आवश्यक है।

② कमाते हुए सीखना : - आधुनिक जीवन कठिन हो गया है। जीवन की आधारभूत आवश्यकताएँ इतनी महंगी हो रही हैं कि लोगों को कमाते हुए सीखना पड़ता है। इसके लिए नियमित महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अतः अधिगम के लिए उन्हें प्रायःकालीन संस्थाओं या पत्राचार कोर्सों की शरण में जाना पड़ता है।

③ स्वतंत्र शिक्षा की इच्छा : - स्वतंत्र रूप से अपनी गति तथा अपने समय के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा ने लोगों को पत्राचार शिक्षा की ओर आकर्षित किया।

④ शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने की इच्छा : - आधुनिक जीवन में सभी तत्व मिलकर जटिल हो रहे हैं परिणामस्वरूप विभिन्न व्यवसायों की शैक्षणिक योग्यताओं में परिवर्तन आ गया है। इन परिवर्तनों के अनुरूप अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाना प्रत्येक व्यक्ति की स्वभाविक इच्छा है। पत्राचार कोर्स विभिन्न व्यवसायों से संबंधित व्यक्तियों को अपनी शैक्षणिक योग्यताएँ बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं।

⑤ लचीलापन : - नियमित शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा पद्धति में लचीलापन कम होने के कारण, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है।

दूरस्थ शिक्षा की समस्याएँ और उन्हें दूर करने के उपाय : -

① आवश्यकता - आवश्यकता के आधार पर कौर्से का चयन होना चाहिए। किसी कौर्से को आरंभ करने के पहले इसकी संभावित उपयोगिताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

② पाठ्य - सामग्री की तैयारी की समस्या - पाठ्य सामग्री की तैयारी कूरस्थ शिक्षा की मुख्य समस्याओं में से एक है, पाठ्य सामग्री को प्रादेशिक भाषा में तैयार किया जाना चाहिए।

③ पाठ्य-सामग्री को समय पर तैयार करने और भेजने की समस्या : - इस समस्या को सुलझाने के लिए यह निश्चित किया जाना चाहिए कि पाठ्य - सामग्री को समय पर तैयार किया जाए और उचित रूप में भेजा जाए।

④ डाक संबंधी अधिकारियों के साथ समन्वय की समस्या - पाठ्य सामग्री को भेजने के लिए डाक अधिकारियों के साथ उचित नियोजन एवं समन्वय की आवश्यकता है।

⑤ प्रदर्शन कार्यों की नियमित जांच और उनके अंकन की समस्या - कूरस्थ शिक्षा की सफलता काफी हद तक ध्यानपूर्वक तैयार किए गए पाठों की नियमित जांच और द्वात्रों द्वारा प्रदर्शन कार्यों के ईमानदारी से किए जाने पर निर्भर करती है। छात्रावास संस्थानों में प्रदर्शन कार्यों की द्वात्रों एवं अध्यापक द्वारा जांचिता से नहीं लिया जाता है। कोई। विद्यविद्यालय द्वारा बल दिया जाना चाहिए कि प्रदर्शन कार्यों की कुल संख्या में से कम से कम 50% को द्वात्रों द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए।

खुली शिक्षा : - खुली अथवा मुक्त शिक्षा कूरस्थ शिक्षा की वह प्रणाली है जो औपचारिक शिक्षा के बंधनों से मुक्त है, और जिसके तार प्रणाली के लिए खुले हैं। मुक्त शिक्षा शिक्षा संबंधी एक नवाचारी आंदोलन एवं शिक्षा सुधार है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंदर अधिगम के अवसरों में बढ़ि करता है। इसके आज शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण जगह बना ली है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (N.J.O.S), भारत के मुक्त विद्यालयों की शिक्षा - परिषद है। यह एक स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1989 के नवंबर में हुई थी। इसका उद्देश्य देश के सुकूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सस्ती शिक्षा सुलभ कराना है।

Q (10) वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली की चर्चा करें :-

Ans: - वैदिककालीन काल शब्द से स्पष्ट होता है कि "वेदों का समय"। वैदिक काल का समय निश्चित करने के लिए अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। इस बात को भी सभी विद्वान स्वीकार करते हैं कि लगभग 2500 ईपू पूर्व से 500 ईपू पूर्व तक वेदों का वर्चस्व रहा। इसी को वैदिक काल का समय माना जाता है। और इस काल की शिक्षा प्रणाली को वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। यह शिक्षा प्रणाली वैदिक धर्म व वैदिक दर्शन पर ही आधारित थी।

वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली तथा हिन्दू शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में ब्राह्मणों का शिक्षा पर एक दृष्ट अधिकार था। पूरे वैदिक काल में शिक्षा की संरचना समान थी लेकिन समय परिवर्तन व परिस्थिति के अनुसार पाठ्यचर्चा व शिक्षण विधियों तथा कला कौशल में कुछ परिवर्तन हुआ। वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। वेदों में कहा गया है कि "सा विद्या या विमुक्तये" अर्थात् विद्या वह है जो कि मुक्ति दिलाती है। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का नैतिक, लौकिक व आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर मोक्ष प्राप्ति करना था। इसके लिए साधना की जाती थी। जिसके अन्तर्गत यज्ञ, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, चारणा, ध्यान व समाधि योग पर विशेष बल दिया जाता था। इस काल में शिक्षा द्वारा आध्यात्मिक और लौकिक जगत के बीच समंजस स्थापित कर धर्म व्यवस्था द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति की जाती थी। तथा शिक्षा को ब्रह्म प्राप्ति का एक साधन माना जाता था।

वैदिक काल में केवल दो प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ① प्रारंभिक शिक्षा ② उच्च शिक्षा।

① प्रारंभिक शिक्षा :- वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा बच्चे को 5 वर्ष की अवस्था में विद्यारम्भ संस्कार के साथ ही जाती थी।

विद्यारम्भ संस्कार :- यह संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में बालक को स्नान कराकर, त्र्ये वस्त्र पहनाकर, कुल पुरोहित के पास ले जाया जाता था। कुल पुरोहित किसी वस्त्र में चावल बिटाता था और उग्र-चावल में बालक की उँगली पकड़कर वर्णमाला के आधार ब्रजवाता था तथा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था। इस प्रकार बच्चे की नियमित शिक्षा प्रारंभ होती थी।

② उच्च शिक्षा : - इस काल में उच्च शिक्षा अशकुलों में ही जाती थी। अशकुल में प्रवेश की आयु 8 वर्ष से 12 वर्ष थी। अशकुल में प्रवेश करते समय "उपनयन संस्कार" कराया जाता था। उपनयन संस्कार - उपनयन का अर्थ है 'समीप लाना' अर्थात् अशु के समुप ले जाना। यह संस्कार ब्राह्मण की के बच्चों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय वर्ग के बच्चों के लिए 10 वर्ष तथा वैश्य वर्ग के बच्चों को 12 वर्ष की अवस्था में कराया जाता था। इस दिन बालक का सिर मुंडवाकर पीला वस्त्र धारण कराये जाते थे तथा यज्ञोपवीत (जनेऊ) कराया जाता था। तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा दी जाती थी।

वैदिककालीन शिक्षा का प्रशासन अशु पर ही निर्भर करता था क्योंकि अशकुल की देखरेख व व्यवस्था करना अशु का उत्तरदायित्व था। वैदिक काल में शिक्षा की प्रकृति के आधार पर दो रूपों में विभाजित किया गया है।

① परा पाठ्यचर्चा : - इस पाठ्यचर्चा के अंतर्गत आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। जैसे शास्त्र, नीति-शास्त्र, वेद, उपनिषद्, ईश्वर भक्ति, यज्ञ आदि। अर्थात् जिससे आध्यात्मिकता का विकास हो सके।

② अपरा पाठ्यचर्चा : - इसके अन्तर्गत अन्य विषय जैसे भाषा, साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, बुनाई, धातु कार्य, राजनीति शास्त्र, सैनिक शिक्षा दी जाती थी।

इस प्रकार अंत में कहा जा सकता है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव का पथर है। वास्तव में देखा जाय तो वैदिक शिक्षा प्रणाली हमारी संस्कृति पर आधारित थी। और हम अपनी संस्कृति से अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारी शिक्षा का वर्तमान उद्देश्य भी वही है जो वैदिक काल में था। दारा सादत जहाँगीर स्मारक चारखान माला में भाषण करते समय श्री लक्ष्मण स्वामी मुद्रालियर ने कहा था - "हम भारतवासियों को अपनी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को पहचानना चाहिए और अनेक्य में आने वाली पीढ़ियों को उसकी वास्तविक आत्मा को स्वीकार करना चाहिए।"

Q(11.) वर्धा शिक्षा योजना (क्रियाशील शिक्षा) 1937 पर टिप्पणी लिखें ।

Ans. - गांधी जी ने भारतीय शिक्षा में व्याप्त तत्कालीन दोषों को दूर करने के लिए क्रांतिकारी पहल की । गांधी जी के शैक्षिक विचार, उनके शिक्षा संबंधी प्रयोगों पर आधारित हैं । गांधी जी ने 1936 ई० में 'हरिजन' पत्र द्वारा अपने विचार का प्रचार करना आरंभ किया । 22 व 23 अक्टूबर पर 1937 में वर्धा के पैठ जमनालाल बजाज के मारवाड़ी हाईस्कूल की रजत जयंती पर नवीन शिक्षा पर विचार करने के लिए गांधी जी के प्रभापतित्व में एक 'अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन' का आयोजन किया गया जिसमें देश के शिक्षाशास्त्री, राष्ट्रीय नेताओं एवं समाज सुधारकों को आमंत्रित किया गया । इसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है । गांधी जी ने इस सम्मेलन में अपने शिक्षा संबंधी विचार व्यक्त किए । सम्मेलन में इस विषय पर पर्याप्त विचार विमर्श हुआ और अन्ततः कुछ प्रस्ताव पारित हुए जिनमें क्रियाशील शिक्षा के प्रारंभ में निम्नलिखित की संज्ञा दी गई ।

'शैक्षिक शिक्षा योजना' अथवा 'वर्धा योजना' की रूपरेखा इस प्रकार है :-

- 1) शैक्षिक शिक्षा की पाठ्यक्रम अवधि 7 वर्ष की है ।
- 2) यह शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बालकों और बालिकाओं के लिए अनिवार्य और अनिवार्य है ।
- 3) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है ।
- 4) सम्पूर्ण शिक्षा का संबंध किसी आधारभूत शिल्प से होता है ।
- 5) चुने हुए शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाती है कि वह बालकों को अच्छा शिल्पी बनाकर, उनको स्वावलंबी बना देती है ।
- 6) पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है ।
- 7) शिल्प की बालकों की योग्यता और स्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चुना जाता है ।

उद्देश्य : - वर्धा शिक्षा योजना के निम्न उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

- 1) नागरिकता का विकास - लोगों को शासन के प्रति अधिकृत्य व अधिकार के लिए जागरूक करना ।
- 2) शरीर, मन, आत्मा तीनों का विकास : - गांधी जी रूढ़िवादी विकास के पक्ष में न थे, बल्कि वह व्यक्ति के शरीर, मन, व आत्मा का एक साथ विकास करना चाहते थे ।
- 3) चरित्र का विकास : - गांधी जी ने लिखा है कि यदि शुरु से

कोई पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है तो मैं उत्तर दूंगा कि (-चरित्र का विकास)। इसलिए उन्होंने इस उद्देश्य पर अधिक बल दिया है।

④ आत्मबोध :- गांधी जी ने शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मबोध माना है।

⑤ मानव स्वभाव की पूर्णता :- गांधी जी ने शिक्षा का सबसे महान उद्देश्य मानव स्वभाव की पूर्णता कहा है।

बुनियादी शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत :-

① त्रि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा - गांधी जी शिक्षा को प्रमुख का जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। अतः बुनियादी शिक्षा में उन्होंने 7 से 14 वर्ष के बालक - बालिकाओं को त्रि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रारंभ किया।

② आत्मनिर्भरता पर आधारित - ब्रिटिश कालीन शिक्षा में बालक को आत्मनिर्भर बन बनाया जाता था क्योंकि वह शिक्षा मुक्त: सैद्धांतिक ही जिसका मुख्य उद्देश्य बालक पैदा करना था न कि उसे आजीवन के लिए तैयार करना। अतः इस बुनियादी शिक्षा में बालक एवं बालिकाओं को विभिन्न उद्योगों एवं हस्तकलाओं की शिक्षा प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाया जायेगा।

③ शिक्षा का मातृभाषा माहौल - बुनियादी शिक्षा में अंग्रेजी की जगह मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की अवकालत की गई।

④ सामाजिक शिक्षा पर आधारित - बुनियादी शिक्षा में ऐसे समाज का निर्माण करने पर जोर दिया गया है जो स्वार्थ एवं शोषण से रहित प्रेम एवं न्याय पर आधारित ही तथा प्रत्येक एवं अहिंसा का अनुसरण करता है।

⑤ वर्ग रहित समाज का निर्माण - ब्रिटिश कालीन शिक्षा द्वारा भारतीय समाज में वर्ग-भेद पैदा किया जाता था। अतः बुनियादी शिक्षा द्वारा वर्ग रहित समाज के निर्माण पर बल दिया गया।

⑥ सम्पूर्ण ज्ञान को एक इकाई में विकसित करने पर आधारित - गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा में सम्पूर्ण ज्ञान को एक पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने पर जोर दिया।

Q.19.) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (राधाकृष्णन कमीशन 1948-49) पर लिखनी करें।

किसी - इस आयोग का प्रमुख कार्य था भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा उन सुधारों एवं विकासों के विषय में सलाह देना था जो देश की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप होने के लिए उपयुक्त हो।

सरकार ने 4 नवंबर 1948 को 'विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग' की नियुक्ति इसके अध्यक्ष डॉ० सर्वपल्लवी राधाकृष्णन को। आयोग से लगभग 20 विषयों की जांच करने के लिए कहा गया था, जिनमें ये मुख्य हैं :-

- 1) भारतीय विश्वविद्यालय के संगठन, नियंत्रण, कार्य-क्षेत्र एवं विधान के संबंध में आवश्यक परिवर्तन।
 - 2) विश्वविद्यालय की शिक्षा की अवधि, माध्यम एवं पाठ्यक्रम।
 - 3) प्रादेशिक या अन्य आधार पर अधिक विश्वविद्यालय की स्थापना।
 - 4) भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य के उद्देश्य।
 - 5) विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबंध कालेजों में शिक्षा एवं परीक्षा के स्तरों में सुनयन।
 - 6) छात्रों के अनुशासन, छात्रावासों, उपकक्षा-कार्य आदि का संयोजन।
 - 7) विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा।
 - 8) अध्यापक की योग्यताएँ, सेवा-शर्तियाँ, वेतन, कार्य एवं अधिकार।
- आयोग ने इन कार्यों को एक वर्ष से कम समय में ही पूरा कर 25 अगस्त 1949 ई० को अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को भेज दिया।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशें :-

- 1) विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन।
- 2) विश्वविद्यालय में कम से कम 180 दिन की पढ़ाई हो यह एकमात्र 11-11 सप्ताहों के तीन भागों में बँटा होना चाहिए।
- 3) प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं है।
- 4) शिक्षा की सार्वभौम सुविधा में रखने का सुझाव।
- 5) उच्च शिक्षा के तीन मुख्य उद्देश्य - सामान्य शिक्षण, संस्कृति

शिक्षण और व्यवसायिक शिक्षण हो।

(6) कृषि, वाणिज्य, विद्या, अभियांत्रिकी तथा प्राविधिक और आधुनिक पर अधिक बल देना चाहिए।

(7) विश्वविद्यालय की देख रेख हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - 1953 ई० में राधा कृष्ण आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई। 1956 ई० में संसद के अधिनियम के द्वारा आयोग को स्वायत्त पूर्ण परिनिष्पन्न पद दे दिया गया।

(8) ग्रामीण विश्वविद्यालय :- हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। अतः उसकी उन्नति एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण कॉलेज एवं ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने चाहिए। ग्रामीण विश्वविद्यालय की आवश्यकता एवं महत्ता पर बल देते हुए आयोग ने लिखा है कि - "ग्रामीण भारत की सामान्य उन्नति के लिए कुशलता और प्रशिक्षण की वीणा तथा गुण में निरंतर विस्तार करना होगा। इसकी प्रदान करने के लिए और शिक्षित नागरिकों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए ग्रामीण कॉलेज और विश्वविद्यालय की पद्धति आवश्यक है। अतः इस दिशा में कार्य करना वांछनीय है।"

(9) आयोग ने इस संदर्भ में निम्न सुझाव दिये :-

(a) ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे स्नातक पूर्ण कॉलेजों की स्थापना करके, उनके केन्द्र में एक ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए।

(b) ग्रामीण कॉलेज का प्रमुख उद्देश्य दार्शनीयों की सामान्य शिक्षा देने के साथ-साथ उसकी स्थानगत रुचियों व मनोवृत्तियों का अधिकतम विकास किया जाना चाहिए।

(c) कॉलेज में पढ़ने वालों की संख्या लगभग 3000 हो और सरकारी कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के दार्शनीयों की संख्या 2500 से अधिक न हो।

(d) ग्रामीण विश्वविद्यालयों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के दार्शनीयों की सामान्य शिक्षा देने के साथ-साथ उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या से अवगत कराये तथा उनका निराकरण करने में मार्गदर्शन करें।

Q(13.) भारतीय शिक्षा आयोग (हॉर कमीशन) 1882 पर नोट लिखिए ।

Ans:- बर 1854 ई० में वुड घोषणा पत्र के अनुसार नई शिक्षा नीति लागू की गई थी । लेकिन सरकार उस नीति को ठीक से लागू नहीं कर पायी तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं हो पाई । लार्ड रिपन की सबसे अधिक चिन्ता भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास की थी । इसलिए उन्होंने चार्ल्स वुड के घोषणा-पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दुर्द प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 ई० में डब्लू. हॉर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की । इस आयोग में 7 सदस्य भारत के थे । आयोग को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया था । आयोग की निम्न समस्याओं का अध्ययन करने तथा उन पर अपने सुझाव देने का आदेश दिया गया था ।

① वुड घोषणा पत्र 1854 का पालन किस सीमा तक हुआ और उस नीति में क्या परिवर्तन आवश्यक हैं ?

② भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करना तथा इसके सुधार हेतु सुझाव देना ।

③ भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सरकारी स्कूलों की क्या भूमिका है? इस संबंध में सरकार की नीति क्या होनी चाहिए ?

④ भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मिशन स्कूलों की क्या भूमिका है? इस संबंध में सरकार की नीति क्या होनी चाहिए ?

⑤ भारत में शिक्षा के प्रसार में व्यक्तिगत प्रयासों का क्या योगदान है ? तथा इस संबंध में सरकार की नीति क्या होनी चाहिए ?

⑥ धार्मिक शिक्षा के संबंध में सरकार की नीति क्या होनी चाहिए ।

आयोग ने वुड घोषणा पत्र पर गहराई से अध्ययन किया तथा तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया तथा शिक्षा के सभी बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया और अंत में अपना प्रतिवेदन तैयार कर 1883 में सरकार को प्रेषित किया । यह प्रतिवेदन 370 पृष्ठों का है जिसमें शिक्षा के सभी पदुलों में विचारपूर्वक चर्चा की गई है तथा सुधार के लिए सुझाव दिये गये हैं :-

आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव व सिफारिशों निम्न लिखित हैं :-

① हाईस्कूल स्तर पर दो प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी।
जिसमें एक व्यवसायिक एवं व्यापारिक शिक्षा दिये जाने पर बल दिया जाये तथा दूसरी साहित्यिक शिक्षा दी जाये, जिससे विज्ञानविद्यालय में प्रवेश हेतु गद्ययत्न मिले।

② प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के प्रद्व पर बल एवं स्थानीय भाषा तथा उपयोगी विषय में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये।

③ शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों का स्वागत ही, लेकिन प्राथमिक शिक्षा उसके बगैर भी दी जाये।

④ प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का नियंत्रण जिला व कंगर बोर्ड को सौंप दिया जाये।

⑤ सार्वजनिक कॉलेजों को राजकीय कॉलेजों की क्षमता का अल्प अंश लेने का अधिकार प्रदान किया जाये।

⑥ शिक्षक प्रशिक्षण पर बल दिया जाये व प्रशिक्षण महा-विद्यालय खोले जायें।

⑦ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही।

⑧ बालक शिक्षा, मुस्लिम बच्चों की शिक्षा तथा पिढ़ड़े व गिन्नाजाति के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाये, तथा इन बच्चों की दारुबन्धि दी जाये।

यदि इण्डियन कमीशन के सुझाव व सिफारिशों का प्रत्यांकन किया जाये तो इस, आयोग ने कुछ चर्चणा पत्र 1854 का ही समर्थन किया था। परन्तु साथ ही कुछ सुझाव नये दिये थे जैसे - प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों को सौंपना तथा माध्यमिक शिक्षा का भार कुशल एवं धनी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं को सौंपना। इन सुझावों का दूरगामी परिणाम निकला। निम्नलिखित इष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं कि इण्डियन कमीशन के सुझाव व सिफारिश का लाभ ज्यादा हुआ है और हानियाँ कम हुई हैं। यदि हानियाँ हुई हैं तो वह स्थानीय निकायों की लापरवाही के कारण हुई।

अतः हम कह सकते हैं कि इण्डियन कमीशन यद्यपि भारतीय शिक्षा आयोग का शिक्षा के प्रचार व प्रसार में थापक अयत्न पड़ा।

Q(14.) वुड चौखणा पत्र 1854 की व्याख्या करें ।

Ans:- "वुड चौखणा पत्र को भारतीय शिक्षा के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रचारिका पत्र कहा गया" वुड चौखणा पत्र 1854 से पूर्व भारतीय शिक्षा प्रणाली का रूप अव्यवस्थित था। केवल अंग्रेजी शिक्षा व संस्कृति का प्रचार करना ही शिक्षा का उद्देश्य था। जिससे की कम्पनी में बर्ष करने के लिए अंग्रेज भक्त भारतीय तैयार हो सकें। वुड चौखणा पत्र का उद्देश्य भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान के लाभ-लाभ नैतिक मूल्यों व लौकिक मूल्यों का विकास करना भी था। चौखणा पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि - "अनेक महत्वपूर्ण विषयों में ये अन्य कोई भी विषय इतना आकर्षण उत्पन्न नहीं करता, जितना कि शिक्षा। यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम समस्त उपलब्ध साधनों से भारतीय प्रजा को अपने सम्पर्क (इंग्लैण्ड के) से वह ज्ञान प्रदान करें। जिससे कि वे शिक्षा द्वारा नैतिक एवं नैतिक गुणों से सम्पन्न हो सकें।" इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वुड चौखणा पत्र में पाश्चात्य संस्कृति व शिक्षा के प्रचार के साथ-साथ नैतिक एवं नैतिक गुणों का विकास करना भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। इस दृष्टि से वुड चौखणा पत्र के निम्न उद्देश्य हैं: -

- 1) भारतीय साहित्य को पाश्चात्य दर्शन एवं शिक्षा से सुसज्जित करना।
- 2) भारत में परिमार्जित कला, विज्ञान, दर्शन तथा यूरोपीय साहित्य का प्रचार करना।
- 3) भारतीय को अंग्रेजी ज्ञान वरदान से वञ्चित करना।
- 4) भारतीयों में कम्पनी के कार्यालयों में कार्य करने की निपुणतायें विकसित करना ताकि वे रोजगार, आम एवं पूंजी आदि शक्तों से परिचित हो सकें तथा अधिकों की उचित आपूर्ति जारी रखी जा सके।
- 5) भारतीयों को शिक्षा द्वारा उच्च लौकिक संपत्तयें ही नहीं बल्कि उनके नैतिक मूल्यों को भी विकसित करना। जिससे वे अधिक विश्वासी सिद्ध हो सकें।

वुड चौखणा पत्र के गुण: -

- 1) शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण: - वुड चौखणा पत्र में भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया गया तथा शिक्षा नीति का निर्धारण किया गया ~~क~~ जिससे शिक्षा को एक निश्चित दिशा प्रदान की।
- 2) शिक्षा का उन्नतभावित्व सरकार पर - भारत के शिक्षा के इतिहास में

पहली बार यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। जो वर्तमान परिस्थिति के लिए भी आवश्यक है।

③ स्त्री शिक्षा पर बल - इस घोषणा पत्र में पहली बार देश की उन्नति के लिए स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रथक विद्यालय खोलने की घोषणा की।

④ व्यावसायिक शिक्षा पर बल - इस घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्कूलों, कॉलेजों तथा प्रथक व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव करते देश में करनी हुई खेतीजगती की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया।

⑤ मुस्लिम शिक्षा पर बल - इस नीति में मुस्लिम बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया क्योंकि उस समय मुस्लिम बच्चों का शिक्षा के प्रति कम आकर्षण था।

कुछ घोषणा पत्र के दोष :-

~~①~~ ① शिक्षा के क्षेत्र में लालफीताशाही :- अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होने से शिक्षा के क्षेत्र में लालफीताशाही प्रारंभ ही गया क्योंकि उच्च पदों पर अंग्रेज नियुक्त होते थे तथा कमिष्ठ पदों पर भी अंग्रेज भक्त भारतीय।

② प्राच्य साहित्य पर संकट :- अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की रीजगार मिलने के कारण लोग अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता देने लगे तथा भारतीय साहित्य व विद्यालयों का अस्तित्व संकट में आ गया।

③ सहायता अनुदान की शर्तें कठोर :- इस नीति में सहायता व अनुदान प्रणाली की बुरावत तो हुई लेकिन शर्तें कठोर थी। खिलका लाभ कभी विद्यालयों को नहीं मिल पाया।

④ भारतीय विश्वविद्यालय के आदर्श लंदन विश्वविद्यालय - घोषणा पत्र में नये विश्वविद्यालय की स्थापना करने का बुराव दिया तथा उनकी कार्यप्रणाली व संरचना तथा आदर्श लंदन विश्वविद्यालय को रखा गया जो कि भारतीय वातावरण व परिस्थिति के अनुसार नहीं था।

⑤ शिक्षा के संकुचित उद्देश्य :- कुछ घोषणा पत्र में शिक्षा का संकुचित उद्देश्य नजर आता है क्योंकि इसमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी ज्ञान प्राप्त करके सरकारी नौकरी प्राप्त करना था।

Q.15.) शिक्षा में तकनीकी सशक्तीकरण की व्याख्या करें।

Ans. - शिक्षा तकनीकी सशक्तीकरण :- किसी भी देश के विकसित होने का अर्थ उस देश के नागरिकों के सर्वांगीण विकास से होता है। आज का युग संचार प्रौद्योगिकी विज्ञान तकनीकी का युग है। तकनीकी के बिना किसी भी देश और उसके समाज के विकसित होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 21 वीं शताब्दी में नई तकनीकी का विस्फोट हुआ है जिसने मानव जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है, अभिनव परिवर्तन पद्धति में देश के सभी स्तर पर परिवर्तन किये जायें ताकि मानवान समाज की स्थापना हो सके, तकनीकी नवाचार के उचित प्रयोग से शिक्षण अधिगम तथा प्रशिक्षण में सफलता एवं कुशलता संभव है।

शिक्षा तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है शिक्षा + तकनीकी। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है आत्म प्राप्ताकार है व्यक्ति को निस्वार्थी बनाती है। तकनीकी का संबंध कौशल तथा दक्षता से है। वैज्ञानिक ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करना। शिक्षा तकनीकी - शिक्षा के क्षेत्र में मशीनों नवीन कलाकों, कौशलों, नवीनता का प्रयोग, शिक्षा तकनीकी का आध्यात्मिक विज्ञान तथा तकनीकी है। यह मशीन विज्ञान समाजशास्त्र इंजिनियरिंग तथा भौतिक विज्ञान से प्रभावित होती है। रुसो एवं कुलकर्णी के अनुसार - " तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों के शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को शिक्षा तकनीकी कहा जाता है।

शिक्षा में मशीनों का प्रयोग करना शिक्षा तकनीकी है शिक्षा का प्रसार करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण (टेप रिकार्ड, कम्प्यूटर) का प्रयोग करना, शिक्षा तकनीकी में अनेक प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षण के लिए प्रादुर्भाव तैयार करना छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए उपकरणों के माध्यम से ज्ञान का सुदृढीकरण करना शिक्षा तकनीकी का कार्य है।

तकनीकी सशक्तीकरण का शिक्षा में योगदान :-

—X —X —X —X —

तकनीकी ने मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया है यह शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रान्ति ला रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी ने नये प्रतिमानों को स्थापित किया है शिक्षा एवं शिक्षा प्रक्रिया शिक्षण अधिगम को सरल एवं सहज बना दिया है, तकनीकी के उचित प्रयोग से शिक्षण अधिगम तथा प्रशिक्षण में

कुशलता प्राप्ति संभव है व्यक्ति को अपने विचारों की तकरीकी
अंतों के माध्यम से दूर बैठे अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने में
सहायता मिलती है।

सामाजिक क्षेत्र में योगदान - समाज के क्रियाकलाप कुछ
इस तरह से हैं कि सभी को समान अवसर नहीं मिल पाते
तकरीकी सशक्तीकरण ने सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योग-
दान दिया है आज के लोग भी आसानी से अपनी सामा-
जिक स्थिति सुधारने में सक्षम हैं जिन्हें समाज ने किन्हीं
कारणवश पूर्ण अवसर नहीं मिलते सामाजिक क्रिया कलापों
में तकरीकी अंतों से लोगों को सहायता मिल रही है।

प्रौद्योगिकी दृष्टि से उपयोगी तकरीकी के माध्यम
से अधिगम कर्ता को मानसिक संतुष्टि प्रदान की जा सकती है
जो दाता, अध्यापक की बातों को ~~संश्लेषण~~ अच्छी प्रकार से
नहीं ग्रहण कर पाते या अध्यापक द्वारा प्रयोजितान को नहीं
समझ पाते तब तकरीकी इस कार्य को बहुत ही सहज एवं
सरल बना देती है।

शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है शिक्षा द्वारा मानव में
सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है उसे पूर्ण सामाजिक
प्राप्ति बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः
हम कह सकते हैं कि शिक्षा सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण
चरण के रूप में कार्य करती है, व्यक्ति में ज्ञानात्मक, भावा-
त्मक, क्रियात्मक भावों का विकास कर मानव व्यक्तित्व को
पूर्ण रूप से सशक्त बनाने में दूर संभव प्रयासरत है।

शिक्षा मानव व्यक्तित्व में मानवीय गुणों, मानवीय
मूल्यों, अवधारणा, प्रकृति एवं वर्गीकरण के लिए आवश्यक
है। शिक्षा के द्वारा मानव के विभिन्न पहलुओं का विकास होता
है, विभिन्न योग्यतायें शक्तियों का विकास होता है, जो
सशक्तीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा सशक्ती-
करण करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, शिक्षा की
ज्योति जलाकर, मानव जीवन रोशनी करता है, इस शिक्षा
व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर सशक्त बनाती
है।